बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 151 ● नई दिल्ली ● सोमवार 30 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में आग का तांडव : जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद 4 लोग घायल, फिर मची चीख-पुकार

नई दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में शनिवार देर रात एक इमारत में लगी आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूद जाने के कारण दो साल के बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि भूतल पर खड़े दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में आग लगने के बाद छह मंजिला इमारत में धुआं भर गया और इमारत से आठ लोगों को बचाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना भजनपुरा के पास चांद बाग इलाके के एक ब्लॉक स्थित एक मकान में रात करीब ढाई बजे हुई। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले तीन महिलाएं और एक बच्चा इमारत की पहली मंजिल से कूद गए।

दिल्ली में सस्ती सब्जियां तो किसानों पर भारी मार, प्याज-टमाटर के दाम गिरे, अन्नदाता परेशान

नई दिल्ली। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच पैदा हुए गैस और तेल के संकट के बीच, राजधानी दिल्ली में इन दिनों रसोई का बजट थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के माथे पर शिकन गहरी हो गई है. बाजार में प्याज और टमाटर के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल रही है, जबकि किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है. दिल्ली के खुदरा बाजारों में पिछले करीब तीन महीनों से प्याज की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं. मौजूदा समय में प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो के दायरे में बिक रही है. वहीं, थोक बाजार यानी आजादपुर मंडी में इसकी कीमत और भी कम होकर 8 से 18 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. कीमतों में इस गिरावट ने ग्राहकों को राहत जरूर दी है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसके असर दूरगामी हो सकते हैं. प्याज की बढ़ती सप्लाई का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति कमजोर होती जा रही है. व्यापारियों के अनुसार, मंडी में जहां प्याज 8 से 18 रुपये किलो बिक रही है, वहीं किसानों को खेतों पर सिर्फ 3 से 5 रुपये प्रति किलो का ही भाव मिल पा रहा है. लागत और मेहनत के मुकाबले यह कीमत बेहद कम है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्याज की तरह टमाटर के दाम भी इन दिनों नियंत्रण में हैं. दिल्ली में टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है. अच्छी पैदावार और पर्याप्त आपूर्ति के चलते कीमतों में नरमी बनी हुई है. हालांकि, यह स्थिति किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अधिक उत्पादन के बावजूद उन्हें बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि बाजार में आपूर्ति बढ़ने और मांग अपेक्षाकृत कम रहने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है. आजादपुर मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में प्याज और टमाटर पहुंच रहे हैं. पहले जहां नवरात्रि के दौरान आवक थोड़ी कम हुई थी, अब फिर से तेजी आ गई है और रोजाना 40 से 50 गाड़ियां प्याज की मंडी में पहुंच रही हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार आ रही खेप ने बाजार में संतुलन बिगाड़ दिया है, जिससे कीमतों में गिरावट जारी है. मौजूदा हालात अगर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो किसानों के लिए यह आर्थिक संकट का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन नहीं बना, तो आने वाले समय में खेती से जुड़ी आय पर गहरा असर पड़ सकता है.

दिल्ली में कुत्ते को बिना पट्टा बांधे घुमाने पर 1000 का जुर्माना, रोड पर कूड़ा फेंकने; मवेशी बांधने पर भी एमसीडी सख्त

नई दिल्ली। एमसीडी अधिनियम, 1957 के प्रविधानों के तहत वर्तमान में पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने वाले मालिक पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन लोकसभा में पेश जन विश्वास (प्रविधान संशोधन) विधेयक, 2026 में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यह बदलाव जन विश्वास (प्रविधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिय एवं उद्योग राय मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई संशोधन प्रस्तावित कए गए हैं। संसद में पेश विधेयक में सड़क पर मवेशियों को बांधने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त मकान नंबर को मिटाने या नष्ट करने पर मौजूदा 50 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। अन्य संशोधनों में खतरनाक आतिशबाजी करने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़कर 500 रुपये करने, नगर निगम के अधिकारी को परिसर में प्रवेश करने से रोकने पर जुर्माना बढ़ाकर 50 से 500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

कूड़ा फैलाने वालों पर भी बढ़ा फाइन

स्वच्छता के संदर्भ की बात की जाए तो कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था न करने पर वर्तमान जुर्माने की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने, गंदगी को सड़क पर बहने देना और कूड़ा फेंकने पर जुर्माना मौजूदा 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में इमारतों के संबंध में कहा गया है कि आदेश दिए जाने पर भी खतरनाक संरचना को खाली न करने पर जुर्माना मौजूदा 200 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये किया जाए। विधेयक में पूर्व के अधिनियम की धारा 465 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें उन उल्लंघनों के लिए सामान्य जुर्माना का प्रविधान है, जिनके लिए कोई विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं है। विधेयक में इस धारा के तहत जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने के साथ ही दैनिक निरंतर जुर्माना 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रविवार (5 अप्रैल 2026) को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य लंबित यातायात चालान और नोटिस का त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें और वे आसानी से अपने मामलों का समाधान कर सकें. यह विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी. इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे, जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं. ऐसे मामलों को सरल प्रक्रिया के जरिए मौके पर ही सुलझाने का अवसर दिया जाएगा. लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 05 अप्रैल, 2026 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत राजधानी के सात बड़े कोर्ट परिसरों पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू–में आयोजित की जाएगी. इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को अपने नजदीकी स्थान पर सुविधा मिल सकेगी. लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट पहले से डाउनलोड कर लें. इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है. कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस ने क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चालान डाउनलोड और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दी है. यह लिंक 30 मार्च को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा. प्रतिदिन सीमित संख्या में ही चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

बिना सुनवाई के दो साल जेल में रखना सजा जैसा, अदालत ने हत्या की कोशिश के आरोपी को दी जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी आरोपी को बिना मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए लंबे समय तक जेल में रखना, सजा देने जैसा है। इसी अहम टिप्पणी के साथ अदालत ने पंजाब के एक आरोपी को जमानत दे दी, जो हत्या की कोशिश के मामले में करीब दो साल से जेल में बंद था। अदालत ने माना कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ और जल्द खत्म होने के भी आसार नहीं हैं, तब आरोपी को लगातार जेल में रखना ठीक नहीं है। अदालत ने यह फैसला प्रदीप कुमार उर्फ बानू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि फरवरी 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उस पर हत्या की कोशिश समेत कई आरोप लगाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष 23 गवाहों में से एक भी गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाया है। ऐसे में साफ है कि मुकदमे को पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी. वी. वराले की पीठ ने 13 मार्च के अपने आदेश में कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लगभग दो साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा, तब उसे जेल में बंद रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ट्रायल कैद में रखना, सजा देने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 11 जुलाई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले को देखते हुए कहा कि अब आरोपी को और यादा समय तक जेल में रखना जरूरी नहीं है। अदालत ने माना कि जब गवाहों की जांच शुरू नहीं हुई और मुकदमा जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा, तब जमानत देना उचित है।

अदालत ने कौन सी शर्तें लगाईं?

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाईं। अदालत ने कहा कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के मुताबिक जमानत बॉन्ड भरना होगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट जो दूसरी शर्तें तय करेगा, उनका भी पालन करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी सीधे या परोक्ष रूप से किसी गवाह को धमका नहीं सकता, लालच नहीं दे सकता और न ही किसी को अदालत में सच बताने से रोक सकता है।

अगर आरोपी शर्तें तोड़े तो क्या होगा?

अदालत ने साफ कर दिया कि अगर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ, तो ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह भी निर्देश दिया कि वह मुकदमे की हर सुनवाई में ईमानदारी से उपस्थित रहे, जब तक कि उसे अदालत से छूट न मिली हो। अगर वह बिना उचित कारण के सुनवाई से गायब रहता है, तो इसे भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ उचित आदेश पारित कर सकता है।

क्या जमानत का मतलब आरोपों से राहत है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया कि जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने कहा कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर अंतिम राय नहीं माना जाएगा। यानी मुकदमे की सुनवाई आगे भी चलेगी और अदालत सबूतों तथा गवाहों के आधार पर ही अंतिम फैसला करेगी। फिलहाल शीर्ष अदालत ने सिर्फ इतना माना है कि बिना सुनवाई शुरू हुए आरोपी को अनिश्चित समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है।

भारत की जनता ईरान के साथ है!

दुनिया से लेकर देश तक की सत्ता-सरकारों की चाकर बनी अधिकांश और तथाकथित स्थापित मीडिया दुनिया में जारी विध्वंसक युद्ध में हो रही जानो-माल की तबाही के असली सच को छुपा रही है। अपने आका-सरकारों के कहे झूठ को ही लगातार परोस रही है। लेकिन तब भी कहीं न कहीं से 'सही खबर' वायरल हो ही जा रही है और असली सच सामने आ ही जा रहा है। जिससे खुलकर ये स्पष्ट हो रहा है कि कौन मदांध युद्धोन्माद से मासूम बच्चियों तक के स्कूल पर बमबारी कर कत्लो-गारद मचा रहा है। दुखदायी विडंबना है कि ईरान पर अमेरिका-इज़राइल ने मिलकर भयावह हमलों की बौछार कर दी, उस ईरान को फकत मुस्लिम/इस्लामिक राष्ट्र होने के भारत जैसे देशों में गोदी मीडिया द्वारा विलेन बताकर फर्जी तथ्यों से खबरों की टीआरपी बढ़ाई जा रही है। लेकिन इन सबों से परे ईरान अपने अस्तित्व और अपने लोगों की आज़ादी-संप्रभुता की हिफाज़त के लिए जान की बाज़ी लगाकर तानाशाह और उसके चेलों का 'मुंहतोड़ जवाब' दे रहा है। स्वयंभू विश्व आका-परस्त अमेरिकी और इज़राइली मीडिया के सुर में और भी अधिक सुर मिलाते हुए गोदी-मीडिया पूरी भक्ति से देश राजा और उनके मंत्री-आमलों के हर झूठ को प्रमाणित-प्रसारित करने में जी-जान लगा रही है। उनके कहे अनुसार लोगों को ही कोसा जा रहा है की वे पैनिक हो रहे हैं। दूसरी ओर, वास्तविक खबर यह भी वायरल हो रही है जिसमें बताया-दिखाया जा रहा है कि कैसे दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर किये जा रहे हमलों का ज़ोरदार विरोध कर रहें हैं। साथ ही अपने-अपने देश की सरकारों-सत्ताधीशों पर ट्रंप-नेतन्याहू द्वारा दुनिया को आसन्न विश्व-युद्ध की विभीषिका में झोंकने के पागलपन पर रोक लगाने का दबाव बना रहे हैं। इसी क्रम में भक्त जमात छोड़कर, भारत में भी अमनपसंद लोकतान्त्रिक-जनपंथी ताकतें और युद्ध-विरोधी नागरिक-समाज मुखर होकर सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में 'युद्ध विरोधी अभियान' संगठित कर भारत की सरकार व उसके आला नेताओं से मांग की जा रही है कि वे युद्धोन्माद फैला रहे अमेरिका-इजराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालें। (जो कि अभी तक ज़रा भी नहीं सुना जा रहा है।) साथ ही मौजूदा केंद्र की सरकार द्वारा लगातार झूठ बोलकर गैस-पेट्रोल के संकटों से बदहवास जनता को एक बार फिर लम्बी लम्बी लाइन लगाने को मजबूर किये जाने का भी ज़ोरदार विरोध किया जा रहा है। 24 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में 'नागरिक मार्च' निकालकर साम्राज्यवादी अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले का पुरज़ोर विरोध किया गया। पीयूसीएल, बिहार के आह्वान पर संगठित किये गए इस नागरिक-अभियान में कई सामाजिक व छात्र-युवा-किसान संगठनों तथा ट्रेड्यूनियन एक्टिविस्ट समेत प्रबुद्ध नागरिकों और वामदलों ने सक्रिय भागीदारी निभायी। ईरान पर लादे गए अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ़ विश्व जनता का प्रतिरोध ज़िंदाबाद, हम ईरान के साथ हैं, ट्रंप-नेतेन्याहू से यारी-ईरान से गद्दारी नहीं चलेगी और भारत की जनता ईरान के साथ है! जैसे नारे लिखे पोस्टरों के साथ यह नागरिक-मार्च निकाला गया। जो बुद्ध स्मृति पार्क परिसर के पास जाकर एक 'विरोध-सभा' में बदल गया। विरोध सभा को कई वरिष्ठ नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट, वामदलों के नेताओं सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से ईरान पर किये जा रहे हमलों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में युद्धोन्माद का तनाव पैदा किये जाने के लिए अमेरिका-इज़राइल का तीखा विरोध किया। साथ ही अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्षरत ईरानी जनता द्वारा अपने बचाव के लिए किये जा रहे युद्ध को न्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि- हम ईरान के साथ हैं! इस पूरे मामले में भारत सरकार की निरंतर चुप्पी तथा प्रकारांतर से ईरान पर लगातार हमला कर रहे आक्रमणकारियों के पक्ष में ही खड़ा होने को दुर्भाग्यपूर्ण कारवाई है। जो की लम्बे समय से चली आ रही भारत की विदेश नीति के सर्वथा विपरीत और गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान पर हमले के दो दिन पूर्व ही इस देश के प्रधानमंत्री का इज़राईल जाकर उसे फादरलैंड घोषित कर आना, दुनिया भर में भारत की खिल्ली उड़ा दिया। वक्ताओं ने पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद की दादागिरी और जबरन हस्तक्षेप करने की तीखी निंदा करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अनैतिक ढंग से गिरफ्तार किये जाने को ट्रंप ने नेतृत्व में अमेरिकी शासक वर्गों का वहशियाना कृत्य कहा। अमेरिका द्वारा क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी का भी कड़ा विरोध किया गया। कार्यक्रम से सर्वसम्मत स्वर में मांग की गयी कि- ईरान पर हमले अविलम्ब बंद किये जाएँ तथा अब तक हुए भारी जानो-माल की तबाही के लिए ट्रंप-नेतान्याहू विश्व की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। हर मामले में हिन्दू-मुसलमान राजनीति के जानलेवा दिमागी-वायरस के एडिक्ट हाईली एक्स्पोस्ड-हाईटेक सुविधासंपन्न ताली-थाली बजानेवाले नागरिक समूह जो बेज़ार बना बैठा था कि 'खाड़ी क्षेत्र के रक्त-रंजित तनाव' से उसे क्या लेना? मामला तो विश्व-आका और फादरलैंड बनाम मुस्लिम देश का है, अब उस आग की तपिश जब उसे घेरकर असहाय बनाने लगी है तो बेचैनी शुरू हो गयी है। उधर, देश के राजा ने भी कह दो-टूक अंदाज़ में कह दिया है कि- कोरोना-काल में जैसे एकजुट हुए थे (बेबसी झेले थे), वैसे ही तैयार रहना है! अर्थात आपदा में अवसर बनाने की कवायद में लग जाना है। सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा हर दिन प्रेस-वार्ता करके ऐलानिया कहा जा रहा है- ऑल ईज़ वेल पैनिक न होवें! जबकि खुद सरकार ने ही एस्मा लगाकर और गैस के दाम बढ़ाकर विपत्ति आने का शोर मचाया। नतीजतन परेशान-हाल जी रहे आम लोगों में बदहवास होने लगे हैं। दुनिया भर के अमनपसंद लोगों ने खुली आँखों से देखा कि कैसे स्वयंभू विश्व-आका और उसके दुलारे देश ने मिलकर ईरान पर हमला बोलकर उसके बड़े नेताओं से लेकर मासूम स्कूली बच्चियों तक का संहार किया।

हमारा संगीत, गीत कहां जा रहा है?

आज के समय में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह समाज की सोच और दिशा को भी प्रभावित करता है। संगीत का सीधा प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। जब गानों में ऐसे शब्द होते है जो रिश्तों, सम्मान और संस्कारों के खिलाफ जाते है तो यह धीरे-धीरे समाज की सोच को भी बदल देते है। आज के युवा इन्हें सुनकर उसी दिशा में सोचने लगते है, जो चिंता का विषय है। कलाकार समाज का आइना होते है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे गाने बनाएं जो प्रेरणा दें, न कि भ्रम या गलत संदेश फैलाएं। केवल प्रसिद्धि या पैसे के लिए किसी भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि हर लोकप्रिय चीज सही नहीं होती। ऐसे गानों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो हमारी संस्कृति और नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं। संगीत का उद्देश्य हमेशा सकारात्मकता प्रेम और संस्कारों को बढ़ावा देना होना चाहिए। आज का संगीत सन् 1980 से पहले के मिठास भरे और नैतिकता से लबरेज संगीत से बहुत अलग है। पहले लोग संगीतकारों और गायकों को याद करते थे और आज टेक्नोलॉजी के चलते सी. रामचन्द्र, शैलेन्द्र, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, कल्याण जी-आनंद जी, लक्ष्मीकांत-प्यारे लाल तथा स्वर कोकिला लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफी तथा मुकेश जैसे संगीतकार और गायक भी नहीं रहे। आजकल संगीत नीरस हो चुका है तो इसकी वजह गायकों का जरूरत से ज्यादा लोकप्रियता पाने के लिए अश्लील गाने प्रस्तुत करने की होड़ है। कदम-कदम पर विवादों के बीच कोर्टों की शरण ली जा रही है। पिछले दिनों बॉलीवुड और भारतीय संगीत उद्योग में दो प्रमुख विवादों ने जोर पकड़ लिया है, जिनमें नोरा फतेही और बादशाह मुख्य केंद्र में हैं। ये विवाद अश्लीलता, महिलाओं के चित्रण और मनोरंजन उद्योग में नैतिकता की सीमाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ रहे हैं। नोरा फतेही का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' और बादशाह का हरियाणवी गाना 'टटीरी' दोनों ही अश्लीलता से भरे पड़े हैं। यदि दृश्यों के कारण कानूनी ये गीतकार व कलाकार सामाजिक निशाने पर आ गए हैं। आखिर हम कहां जा रहे हैं? समाज को यह क्या हो गया है? नोरा फतेही का गाना 'सरके चुनर', जो कन्नड़ फिल्म 'डेविल' का हिंदी संस्करण है, रिलीज के तुरंत बाद विवादों में घिर गया। इस गाने में नोरा के साथ संजय दत्त हैं। आरोप है कि इसके बोल बेहद अश्लील, यौन रूप से आपत्तिजनक हैं। इस गाने को लेकर वकीलों ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से शिकायत की थी। विवाद के मुख्य कारण- गाने के दृश्यों में डांसर बार जैसा माहौल और नोरा के नृत्य को 'बेहद भड़काऊ' माना गया। नायिका अर्धनग्न होकर नाच रही है। आखिरकार भारी विरोध और कानूनी नोटिस के बाद निर्माताओं को यूट्यूब से इसका हिंदी संस्करण हटाना पड़ा। फिल्म 'घूसखोर' पंडत को लेकर भी कोर्ट के आदेश से यह विवादित टाइटल हट गया। गीतों और फिल्मों को लेकर विवाद आज आम बात हो गई है। विवाद पैदा करने को एक हिट फार्मूला माना जा रहा है। चर्चित तारिका नोरा ने विवाद के बाद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने यह गाना 3 साल पहले कन्नड़ भाषा में शूट किया था, न कि हिंदी में। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसके हिंदी लिरिक्स की जानकारी नहीं थी और निर्माताओं ने बिना उनकी अनुमति के उनके विजुअल्स एआई जेनरेटिड का उपयोग करके हिंदी संस्करण तैयार किया। उन्होंने निर्माताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कलाकारों को इन स्थितियों में मोहरा बनाया जाता है लेकिन लोग बताएं कि उसे कितने पैसे अश्लीलता के मिले? इस पर वह चुप हैं। यह अभिनेत्री बताए कि वह अश्लीलता की हदें क्यों पार कर रही हैं। इस कड़ी में रैपर बादशाह भी अपने हरियाणवी गाने 'टटीरी' के कारण कानूनी मुश्किलों में फंसे हैं। इस गाने में स्कूल की वर्दी पहनी लड़कियों को आपत्तिजनक तरीके से नचाने और लिरिक्स में 'वल्गर' शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया को ज्यादा व तेजी से फालो करती है तथा गीत वायरल हो जाने के बाद गायक व कलाकार सुर्खियां बटोरते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अश्लीलता और महिलाओं के गलत चित्रण के लिए बादशाह को समन जारी किया तथा उन्होंने माफी भी मांग ली है। बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा महिलाओं या बच्चों को अपमानित करने का नहीं था। उन्होंने गाना यूट्यूब से हटा दिया। सच तो यह है कि ये दोनों विवाद केवल दो गानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह नैतिकता को लेकर एक गहरी चिंता का विषय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अश्लीलता पर संगीतकार और निर्माता अक्सर इसे 'कलात्मक अभिव्यक्ति' कहते हैं लेकिन जब कोई गाना लोगों के बीच चलता है तो उसका बच्चों और युवाओं पर असर पड़ता है। महिला आयोग और महिला संगठनों का तर्क है कि अश्लील सामग्री सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करती है। इन गानों में अक्सर महिलाओं को केवल 'सैक्स' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी क्या नैतिक जिम्मेदारी केवल डांसर (नोरा फतेही) की है या निर्माता-निर्देशक की सरकार और अदालतों के एक्शन के बाद अब अश्लीलता के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। सोशल मीडिया और कानूनों के माध्यम से ऐसे कंटेंट पर लगाम लगाई जा रही है। मेरा मानना है कि संगीत को लेकर रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अश्लीलता दिखाने वालों पर कड़ा दंड तय होना चाहिए।

एक बार सजा बड़े कलाकार को मिल जाएगी तो दोबारा वह जुर्रत नहीं करेगा, यही समय की मांग है।

सम्पादकीय...

ईरान के लिए दिन-रात आंसू बहाने वाले कश्मीरी नेताओं ने कभी पंडितों के साथ क्यों नहीं दिखाई हमदर्दी?

मीरवाइज उमर फारूक ने नयी दिल्ली में ईरान के राजदूत से मुलाकात कर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से मार कर भगाया जा रहा था तब यह संवेदना कहां थी? तब अमन का पैगाम लेकर ये नेता सामने क्यों नहीं आए थे? क्या उस दौर में इंसानियत की जरूरत नहीं थी? क्या तब किसी प्रतिनिधिमंडल को कश्मीरी पंडितों के घरों तक जाने की फुर्सत नहीं मिली थी? सवाल उठता है कि क्यों आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर इतनी सक्रियता दिखती है, लेकिन अपने ही समाज के जख्मों पर सन्नाटा छा जाता है? क्या यह चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं है? क्या एक धर्म विशेष के लिए ही एकजुटता दिखाना अब राजनीति का हिस्सा बन गया है? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं, तो आपने दिल्ली दौरे के दौरान वहां कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में जाकर उनसे क्यों नहीं मिले? अगर मीरवाइज सच में अमन के दूत हैं तो क्या कश्मीरी पंडितों से मिलकर उनसे वापस अपने घर लौटने का आग्रह नहीं करना चाहिए था? देखा जाये तो कश्मीर में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, दान अभियान चलते हैं, बड़े नेता दूतावास पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसा कोई व्यापक अभियान चला? क्या उनके दर्द को उसी गंभीरता से लिया गया? सवाल उठता है कि आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों है? क्यों एक समुदाय के मुद्दे पर भावनाएं उमड़ती हैं और दूसरे पर खामोशी छा जाती है? क्या संवेदनाएं भी चयनात्मक हो गई हैं? जहां तक मीरवाइज के दिल्ली दौरे की बात है तो आपको बता दें कि श्रीनगर से कश्मीर के कई धार्मिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली पहुंचा और ईरान के राजदूत से मुलाकात कर वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे। उन्होंने न केवल संवेदना व्यक्त की, बल्कि ईरान के लोगों के साथ एकजुटता भी दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाते हुए युद्ध की निंदा की और शांति बहाल होने की उम्मीद जताई। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह वही कश्मीर नहीं है जहां कभी हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ कर भागना पड़ा था। क्या यह वही घाटी नहीं है जहां उनके कत्लेआम की खबरें आई थीं। तब यह धार्मिक संगठन, यह मौलाना, यह नेता कहां थे। तब अमन का संदेश क्यों नहीं दिया गया। तब किसी प्रतिनिधिमंडल ने पंडितों के आंसू पोंछने की कोशिश क्यों नहीं की? मीरवाइज उमर फारूक और उनके साथियों ने ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की बात कही। उन्होंने कश्मीर को ईरान ए सगीर तक बताया। यह बयान बताता है कि उनकी सोच किस दिशा में झुकी हुई है। लेकिन क्या उन्हें यह याद नहीं कि कश्मीर की पहचान केवल किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसकी विविधता से रही है। कश्मीरी पंडित उस पहचान का अभिन्न हिस्सा थे और हैं। दिल्ली में ईरानी राजदूत से मिलना, संवेदना जताना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देना आसान है।

विदेश मंत्री की टिप्पणी में हताशा की झलक

मराठी में किताब का शीर्षक था नरकतला स्वर्ग' इसका अंग्रेजी संस्करण अनलाइकली पैराडाइज' के नाम से आ रहा है। किताब में संजय राउत ने कई बेहद विवादित दावे किए हैं। सबसे विवादित दावा यह है कि जगदीप धनखड़ को ईडी के दबाव में उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने लिखा है कि धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर का अपना घर बेचा और उसके पैसे विदेश ट्रांसफर किए। इसके बाद जांच शुरू की। राउत ने लिखा है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ धनखड़ के कुछ करने की कानाफूसी शुरू हुई तो ईडी के अधिकारियों ने धनखड़ से मिल कर उनको फाइल दिखाई। जांच आगे बढ़ाने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक और दिलचस्प दावा राउत ने यह किया है कि शरद पवार ने अमित शाह की सबसे ज्यादा मदद की। उन्होंने लिखा है कि जब अमित शाह की जमानत नहीं हो रही थी तब शरद पवार ने उनको जमानत दिलवाई थी। उन्होंने किताब में लिखा है कि महाराष्ट्र कैडर का एक सीबीआई अधिकारी जमानत का जबरदस्त विरोध कर रहा था। तब नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन करके मदद मांगी थी और सबकी मदद करने वाले स्वभाव के मुताबिक शरद पवार ने मामले में दखल दिया और अमित शाह की जमानत कराई। किताब में नरेंद्र मोदी से जुड़े किस्से भी हैं।

ईरान युद्ध पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज रस्म-अदायगी भर रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बैठक से दूर रहे। ऐसी बैठकों की तभी अहमियत होती है, जब उनका मकसद उत्पन्न परिस्थिति पर पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सभी पक्षों के बीच आम-सहमति बनाना होता है। ऐसा तभी हो सकता है, जब देश का शीर्ष नेता बैठक में उपस्थित रहे और सिर्फ तभी किसी संकट काल में पूरा देश एक स्वर में बोल सकता है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में ऐसी राष्ट्रीय एकजुटता दुर्लभ होती चली गई है। नतीजतन, सर्वदलीय बैठकें सियासी नैरेटिव को प्रसारित करने का एक और मौका बन जाती है। ईरान युद्ध पर बुलाई गई बैठक का भी यही हाल हुआ। विपक्ष ने उसे अपने इस कथानक को बल देने का अवसर बनाया कि मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलताओं ने भारत को गहरी मुसीबत में डाल दिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत अप्रासंगिक होता जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मध्यस्थ बन कर उभरने की चर्चा हुई तो उस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जो टिप्पणी की वह बेहद हैरतअंगेज रही। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह 'दलाली' नहीं कर सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों मध्यस्थ बनाया, यह दीगर सवाल है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को दलाली बताना अपनी विदेश नीति की घोर विफलता से पैदा हुई हताशा का ही इज़हार समझा जाएगा। वरना, कोरिया युद्ध, कांगो युद्ध, श्रीलंका के गृह युद्ध आदि में मध्यस्थता का भारत का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। इसलिए जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि आज अंतरराष्ट्रीय मसलों में भारत की कोई भूमिका क्यों नहीं है?

चुनाव आयोग को किस बात का डर है?

चुनाव आयोग ने कमाल ही किया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद उसने जिन लोगों के नाम विचाराधीन श्रेणी में रखे हैं उनके दस्तावेजों की जांच करके पूरक मतदाता सूची जारी करने में उसे इतनी परेशानी हुई है कि सब हैरान हैं। चुनाव आयोग ने पहले तय किया था कि 21 मार्च को पहली पूरक मतदाता सूची जारी होगी। शाम तक इंतजार होता रहा और आयोग ने सूची जारी नहीं की। इसके बाद खबर आई कि 23 मार्च को पूरक मतदाता सूची जारी होगी। इस बार आयोग पर दबाव भी था क्योंकि नामांकन शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने आधी रात के ठीक पहले यानी घड़ी में तारीख बदलने से ठीक पहले पूरक मतदाता सूची जारी की। आयोग की ओर से सिर्फ इतना बताया गया कि उसने 29 लाख नामों की जांच की है। उसने यह नहीं बताया कि इसमें से कितने नाम कटे हैं। अब लोग खोज कर पता लगाएं कि उनका नाम कटा है या बचा है। सवाल है कि इतना डर या घबराहट किस बात की है? जानकारों का कहना है कि शनिवार को ईद की वजह से चुनाव आयोग ने पूरक सूची टाल दी थी क्योंकि कुछ अधिकारियों डर था कि ईद के दिन अगर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं खास कर मालदा और मुर्शिदाबाद के मतदाताओं के नाम कटने की खबर आएगी तो विवाद हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह कितनी चिंताजनक बात है?

भाजपा के प्रचार से दूर मुस्लिम नेता

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम नेताओं को चुनाव प्रचार से दूर रखा है। वैसे भी बंगाल में भाजपा के पास ज्यादा मुस्लिम नेता नहीं है और जो हैं उनका भी कद बड़ा नहीं है। इस बार उन सबको प्रचार से दूर रखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी इस बार पूरी तरह से ध्रुवीकरण के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्दी ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आगे भाजपा के प्रचार की लाइन यही रहने वाली है। उसे बांग्लाभाषी हिंदुओं के मन में यह डर पैदा करना है कि मुस्लिम आबादी और घुसपैठ बढ़ने से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी 294 में से एक भी सीट पर किसी मुस्लिम को अपवाद के तौर पर भी टिकट नहीं देगी। उसे राज्य के 70 फीसदी हिंदुओं को मैसेज देना है। भाजपा दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनावों से देख रही है कि जितना हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है उससे वह चुनाव नहीं जीत सकती है। अभी 100 में से 60 हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है। उसे कम से कम 100 में से 70 हिंदू वोट की जरूरत है। इतने बड़े ध्रुवीकरण के लिए भाजपा को जो कुछ भी करना होगा, वह करेगी।

तमिलनाडु में भाजपा को मनचाही सीटें नहीं मिलीं

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया। उसने ई पलानीस्वामी से कई नेताओं के विरोध के बावजूद उनको एनडीए में जोड़ा और एक मजबूत गठबंधन बना कर डीएमके-कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी की। लेकिन खबर है कि भाजपा को खुद भी अपनी पसंद की सीटें लड़ने के लिए नहीं मिलीं। पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना डीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने भाजपा को ज्यादा मुश्किल सीटें दी हैं। सिर्फ भाजपा को ही नहीं, बल्कि दूसरी सहयोगी पार्टियों को भी कठिन सीटें मिली हैं। अगर संख्या की बात करें तो जरूर भाजपा को पिछली बार की 20 सीट के मुकाबले 27 सीटें मिली हैं लेकिन वे पसंद की सीटें नहीं हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा कोयम्बटूर की तीन सीटें चाह रही थी, जिसमें एक सीट सिंगानालूर सीट भी है, जहां से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई लड़ना चाहते थे। लेकिन अन्ना डीएमके ने वह सीट भाजपा के लिए नहीं छोड़ी। उसने कोयम्बटूर में भाजपा को तीन की बजाय सिर्फ एक सीट दी। इसी तरह भाजपा शहरी इलाकों में और खास कर राज्य के पश्चिम हिस्से में सीटें चाहती थी लेकिन अन्ना डीएमके ने ऐसा नहीं होने दिया। अंबुमणि रामदौस की पीएमके को 18 और जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस को सात सीटें मिली हैं लेकिन सबको पलानीस्वामी ने अपने हिसाब से सीटें दी हैं। अन्ना डीएमके खुद 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

राउत की किताब में दिलचस्प खुलासे

उद्धव ठाकरे की शिव सेना के सांसद संजय राउत बेहद दिलचस्प व्यक्ति हैं। कुछ समय पहले राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे काफी समय जेल में रहे थे। जेल में उन्होंने एक किताब लिखी, जिसमें कई दिलचस्प किस्से हैं। मराठी में लिखी गई किताब का अब अंग्रेजी संस्करण आ रहा है तो उसकी चर्चा तेज हो गई है। मराठी में किताब का शीर्षक था नरकतला स्वर्ग' इसका अंग्रेजी संस्करण अनलाइकली पैराडाइज' के नाम से आ रहा है। किताब में संजय राउत ने कई बेहद विवादित दावे किए हैं। सबसे विवादित दावा यह है कि जगदीप धनखड़ को ईडी के दबाव में उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने लिखा है कि धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर का अपना घर बेचा और उसके पैसे विदेश ट्रांसफर किए। इसके बाद जांच शुरू की।

राउत ने लिखा है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ धनखड़ के कुछ करने की कानाफूसी शुरू हुई तो ईडी के अधिकारियों ने धनखड़ से मिल कर उनको फाइल दिखाई। जांच आगे बढ़ाने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक और दिलचस्प दावा राउत ने यह किया है कि शरद पवार ने अमित शाह की सबसे ज्यादा मदद की। उन्होंने लिखा है कि जब अमित शाह की जमानत नहीं हो रही थी तब शरद पवार ने उनको जमानत दिलवाई थी। उन्होंने किताब में लिखा है कि महाराष्ट्र कैडर का एक सीबीआई अधिकारी जमानत का जबरदस्त विरोध कर रहा था। तब नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन करके मदद मांगी थी और सबकी मदद करने वाले स्वभाव के मुताबिक शरद पवार ने मामले में दखल दिया और अमित शाह की जमानत कराई। किताब में नरेंद्र मोदी से जुड़े किस्से भी हैं।

जब भाजपा को नकवी याद आए?

सियासत भी विभिन्न संयोगों का अनोखा मिलन है, किसका रूठा वक्त कब वाचाल होकर गूंज की शक्ल अख्तियार कर ले कहना मुश्किल है। भाजपा के एक बड़े शिया नेता मुख्तार अब्बास नकवी को उनकी ही पार्टी ने एक लंबे वक्त से ठंडे बस्ते में डाल रखा था।

पर जब इस दफे पश्चिम एशिया का संकट गहराया और ईरान संग भारत के रिश्ते कुछ अजीब से पेचोखम में उलझ गए, तो इस गांठ-गिरह को सुलझाने की जिम्मेदारी यकबयक सियासी तौर पर बिसरा दिए गए नकवी के कंधों पर आन पड़ी। भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहाली से नकवी का पुराना राब्ता है, सो रोज़ा-इफ्तार की दावत के बहाने जब नकवी फतहाली से मिलने पहुंचे तो इन दोनों के बीच एक बंद कमरे में आधे घंटे की सारगर्भित बातचीत हुई। नकवी डॉ. फतहाली को यह समझाने में कामयाब रहे कि 'भारत-ईरान के हजारों साल के सांस्कृतिक रिश्ते चंद मौजूदा वाकयों से तार-तार नहीं हो सकते।' फिर नकवी ने कई पुराने घटनाक्रमों का हवाला देते हुए भारत-ईरान के मजबूत रिश्तों की बुनियाद की ओर इशारा किया और कहा 'जब कोरोना अपने उफान पर था तो भारत ने हजारों बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई नागरिकों की भी ईरान से बाहर निकलने में मदद की थी। भारत ने आधे दर्जन से भी ज्यादा अपने विमान तेहरान भेजे थे और लोगों की नागरिकता से दीगर उन्हें भारत लेकर आए थे, जहां जोधपुर के अपने डिफेंस कैंप में एक महीने के लिए इन्हें कोरेंटाइन रखा गया था, इसके बाद उन नागरिकों को उनके संबंधित देशों को भेज दिया गया, क्योंकि उस वक्त ईरान गैर मुल्क के ऐसे नागरिकों को अपने देश के होटलों में रहने की भी इजाजत नहीं दे रहा था। नकवी की यह मुलाकात काम आई, भारत-ईरान के तल्ख रिश्तों पर जमी बर्फ किंचित पिघली और इसके बाद ईरान के भारत स्थित राजदूत का बयान आ गया जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत को एक भरोसेमंद देश बताते हुए कूटनीतिक मध्यस्थता में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद पीएम मोदी की बातचीत भी ईरान के प्रेसिडेंट संग हो गई। फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी डॉ. फतहाली से मिलने पहुंचे। इन घटनाक्रमों की परिणति थी कि ईरान ने होर्मुज पार करने के लिए भारतीय जहाजों को इजाजत दे दी। फिलहाल यह इजाजत चार भारतीय जहाजों को मिली है, आने वाले एक दो रोज में ईरान सभी भारतीय जहाजों को हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है। ईरान ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान को भी प्यार भरा एक तोहफा बताया है। सच में नकवी का यह मुख्तार उपक्रम अपने मुल्क के काफी काम आया। शह-मात की सियासी बिसात पर राजनीति के पगे व धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार को धूल चटाना इतना आसान नहीं, इस बात को अब भगवा रणनीतिकार गण भी समझ गए होंगे। भाजपा नीतीश को नाथ कर राज्यसभा के द्वार तक तो ले आई, पर ये अब भी ऊपरी सदन में शपथ लेने में आनाकानी कर रहे हैं। इन्होंने अभी अपनी विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि वे 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे, उन्हें इन हालातों में अपनी विधान परिषद की सीट छोड़ने के लिए 14 दिनों की मियाद मिली थी, यह अवधि भी इसी 30 मार्च को पूरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश कब दिल्ली का रुख करेंगे? और अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे? तो इस सवाल का जवाब फिलवक्त किसी के पास नहीं। नीतीश से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि 'वे अपने पुत्र निशांत को अपने असली उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार करने में जुटे हैं, इस कार्य में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के 20 पुराने समाजवादी साथियों को लगा रखा है, जिनका कार्य निशांत को एक नई भूमिका के लिए तैयार करना है।' सूत्र यह भी खुलासा करते हैं कि एक नए निशांत के अभ्युदय के लिए देश की एक नामचीन पीआर एजेंसी की भी सेवाएं ली गई हैं, जिन्हें एक भारी भरकम रकम अदा की गई है, निशांत को उनके पिता की पुरानी वीडियो दिखाई जा रही है कि वे लोगों से कैसे मिलते हैं, जनसभाओं को कैसे संबोधित करते हैं, विधानसभा या लोकसभा में वे कैसे बोलते या रिएक्ट करते हैं।

निशांत से अपने पिता की उन भंगिमाओं को लपक लेने को कहा जा रहा है, जिससे कि जब वे जनता के बीच जाएं तो लोगों को उनमें युवा नीतीश की झलक दिखाई पड़े।

जब तक अपनी नई पारी खेलने के लिए निशांत तैयार नहीं हो जाते तब तक नीतीश भाजपा के दिल्ली बुलावे के आमंत्रण को यूं ही टरकाते रहेंगे। असम में सरपट भागती भाजपा की चुनावी रेल यकबयक पटरी से उतरती नज़र आ रही है। इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश के पूर्व भगवा मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बताया जा रहा है। सर्बानंद असम की 'सोनोवाल कचरी जनजाति' से ताल्लुक रखते हैं, राज्य में इनकी आबादी 6.5 फीसदी के आसपास है। यह मैदानी इलाकों में रहने वाली जनजाति है जो अचानक से हिमंता बिस्वा सरमा के विरोध में उतर आई है। यह सब सोनोवाल के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि 'उन्होंने टिकट बंटवारे में सोनोवाल के लोगों की उपेक्षा की है।' असम में इस बार सरमा अपने चेहरे और अपने करिश्मा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका एंटी इंकमबेंसी फैक्टर भी उनके साथ-साथ चल रहा है। ममता ने भी अपनी पार्टी नेत्री सुष्मिता देव की अगुवाई में टीएमसी के 50 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा की भी पार्टी के 20 लोग मैदान में हैं। पहली नज़र में तो लग रहा था कि ये दोनों ही पार्टियां अपरोक्ष तौर पर भाजपा को ही मदद पहुंचा रहीं हैं, पर अब जो जमीनी सर्वे आ रहा है उससे पता चलता है कि कई स्थानों पर इन पार्टियों के उम्मीदवार भाजपा के ही वोट काट रहे हैं, खास कर बोडोलैंड एरिया में। इस चुनाव में हिमंता ने कांग्रेस के कोई 30 लोगों को भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारा है, इससे भी भगवा परेशानियों पर बल पड़ रहे हैं, न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में बल्कि संघ के अनुशासित कैडर में भी इन पूर्व कांग्रेसी उम्मीदवारों को लेकर खासा रोष है। रोहित पवार जो शरद पवार के भतीजे और उनकी ही पार्टी से महाराष्ट्र के विधायक हैं, वे लगातार अपने चाचा अजित पवार के विमान दुर्घटना को एक साजिश करार देने पर तुले हैं। वे काफी पहले ही इस बात की मशक्कत कर रहे थे कि 'इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो।' अपनी इस मांग को लेकर वे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिल चुके थे। पर उनके तमाम प्रयासों के बाद भी राज्य पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया। वे चाहते तो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राज्य में कोर्ट का रुख कर सकते थे, पर उन्होंने देश भर में एक सियासी संदेश देने के लिए दूसरा रास्ता चुना और वे सीधे दिल्ली राहुल गांधी के पास पहुंच गए, जहां राहुल के प्रयासों से कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में 'जीरो एफआईआर' दर्ज हो पाई। दरअसल, अजित पवार के नहीं रहने पर उनकी पार्टी पर नियंत्रण के लिए देवेंद्र फड़णवीस और शरद पवार में अघोषित जंग छिड़ी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा मंच, प्रतिभाओं को मिला सम्मान

रामकोला, कुशीनगर।

जनपद के रामकोला स्थित शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला पीजी कॉलेज एवं आरकेएसएम स्कूल परिसर में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं की रंगारंग एवं आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहरीपुर गोरखपुर की प्राचार्या डॉ. नीरा गुप्ता तथा उदित नारायण पीजी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. ममता मणि त्रिपाठी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों एवं संस्थान के डायरेक्टर राधे गोविंद शाही तथा महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मनीषा सिंह द्वारा मां सरस्वती के

चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात छात्राओं ने गणेश व सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं ने नृत्य, गीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, पत्रकारों एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. संजीत कुमार गुप्ता ने अपने

संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहने तथा लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अभावों के बीच भी सकारात्मक सोच और कर्तव्यनिष्ठा से सफलता प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट अतिथि डॉ. ममता मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जीवन में मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मनीषा सिंह ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम हैं। कार्यक्रम में उप प्रबंधक राधे गोविंद शाही ने मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि वार्षिकोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुनीता पांडे, डॉ. संजय सिंह, श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव, ज्ञानवर्धन गोविंद राव, राम प्रसाद, राम दरस शर्मा, आर.के. भट्ट, मोहम्मद नईम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कुशीनगर में 'विश्व शांति संवाद' का आयोजन- 26 देशों के विद्यार्थियों ने दिया शांति का संदेश

कसया,कुशीनगर। भगवान बुद्ध की निर्वाणस्थली कुशीनगर में विश्व छात्र एवं युवा संगठन एवं मेटा के संयुक्त तत्वावधान में 'विश्व शांति संवाद का भव्य आयोजन किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में 26 देशों के 180 विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर वैश्विक शांति, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरकंटक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. अश्वनी महापात्रा, विश्व छात्र एवं युवा संगठन के अध्यक्ष नितिन शर्मा एवं महासचिव शुभम गोयल शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि WoSY एवं मेटा की संयुक्त पहल पर यह अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी समूह बीते दो दिनों से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 'ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव' में प्रतिभाग कर रहा था, जहां विभिन्न सत्रों के माध्यम से उन्हें आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों ने कुशीनगर पहुंचकर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर 'विश्व शांति संवाद' में हिस्सा लिया तथा बौद्ध भग्नावशेषों का भ्रमण किया। मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब विश्व अनेक समस्याओं–पर्यावरण, गरीबी, कुपोषण, आतंकवाद और युद्ध–से जूझ रहा है, ऐसे समय में 'वसुधैव कुटुंबकम' का भारतीय दर्शन ही इन सभी का समाधान प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि विश्व छात्र एवं युवा संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को एक मंच पर लाना अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शांति के दूत बनकर अपने-अपने देशों में भारतीय संस्कृति के इस संदेश को फैलाएं। विशिष्ट अतिथि प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि कुशीनगर की यह धरती करुणा और प्रज्ञा की प्रतीक है। तकनीकी युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार हो रहा है, तब बुद्ध का 'धम्म' हमें यह सिखाता है कि बुद्धि के साथ संवेदना और नैतिकता का होना भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. अश्वनी महापात्रा ने कहा कि यह 'विश्व शांति संवाद' एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज सूचना के इस युग में ज्ञान तो बढ़ा है, लेकिन विवेक की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। भगवान बुद्ध की यह भूमि हमें आंतरिक संतुलन और शांति का मार्ग दिखाती है, जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अत्यंत प्रासंगिक है।

पडरौना में 'मन की बात' का लाइव प्रसारण- उत्साह के साथ सुना गया प्रधानमंत्री का संदेश

पडरौना, कुशीनगर।

नगरपालिका परिषद पडरौना में रविवार को प्रधानमंत्री Narendra Modi के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' का 132वां एपिसोड बड़े उत्साह और अनुशासन के साथ सुना गया। कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में उनके आवास पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 'ज्ञान भारतम्' ऐप के माध्यम से पांडुलिपियों के संग्रहण, युवा शक्ति, खेल और फिटनेस, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, अरब देशों में युद्ध की स्थिति तथा वर्तमान ईंधन आपूर्ति जैसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनकी ऊर्जा, नवाचार तथा सामाजिक जागरूकता भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्होंने नए वित्तीय वर्ष में नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के उपरांत अपने संबोधन में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास की स्वर्णिम यात्रा पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, खेल और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता एवं मूल्य नियंत्रण को भारत की मजबूत विदेश नीति की बड़ी सफलता बताया तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल सहित संतोष चौहान, रामू पाण्डेय, सनी मिश्र, अनिल पाण्डेय, अभय मारोदिया, सर्वेश उपाध्याय, राजेश जायसवाल, अभिनव चौरसिया, आकाश वर्मा, जयप्रकाश मद्धेशिया, भास्कर पाठक, संदीप निगम, काशी राजभर, अविनाश कसौधन, शिवगोपाल कुशवाहा, परमजीत चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

एबीपीएसएस की बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग

पडरौना, कुशीनगर। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (एबीपीएसएस) की बैठक पडरौना नगर स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। बैठक में संगठन की मजबूती और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से संगठन के विभिन्न पदों पर मनोनयन किया गया। इसमें नियाजुद्दीन अंसारी को जिला सचिव, सरफराज अहमद को वरिष्ठ तहसील उपाध्यक्ष पडरौना, अजित कुमार 'भोलू' को तहसील महासचिव, तालिब अंसारी को सचिव तथा अमित सिंह, सरिता देवी, मनोज कुमार, ताज मोहम्मद, इस्तयाक, असगर अली, विनय कुमार, सलाउद्दीन अंसारी और नीरज को कार्यसमिति सदस्य चुना गया। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है और वह जनता एवं सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष लेखनी ही पत्रकार की वास्तविक पहचान है।

कुशीनगर में बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन का चुनाव सम्पन्न, ध्रुव शर्मा बने अध्यक्ष

पडरौना,कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन (पुरुष) जनपद कुशीनगर का अधिवेशन एवं चुनाव मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण एवं सकुशल वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया में जनपद भर से आए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अधिवेशन के दौरान संगठन की मजबूती, स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बेसिक हेल्थ वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया सर्वसम्मति के आधार पर सम्पन्न हुई, जिसमें ध्रुव शर्मा को अध्यक्ष, विमलेश दुबे

को उपाध्यक्ष, आशुतोष दुबे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सत्य प्रकाश रावत को मंत्री, राकेश कुमार मद्धेशिया को कोषाध्यक्ष, विनोद शाह को संगठन मंत्री, सुमित श्रीवास्तव को सप्रेक्षक तथा अरुण सिंह को संगठन का संरक्षक चुना गया। नव-निर्वाचित अध्यक्ष ध्रुव शर्मा ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन के हितों की रक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया। अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और संगठन की एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना के साथ हुआ।

फाजिलनगर में विधायक पप्पू पांडेय का भव्य स्वागत, राज सिटी स्कैन सेंटर को बताया क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात

पटहेरवा,कुशीनगर। बिहार के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडेय का फाजिलनगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। युवा सामाजिक कार्यकर्ता विनय तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने गाड़ियों के काफिले के साथ तमकुही के झरही नाले पुल पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया और कार्यक्रम स्थल तक अगुवानी की। विधायक पप्पू पांडेय वरिष्ठ पत्रकार उमेश पांडेय उर्फ पिंटू पांडेय द्वारा स्थापित राज सिटी स्कैन सेंटर के शुभारंभ पर शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर फाजिलनगर के विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में विधायक अमरेंद्र पांडेय ने कहा कि फाजिलनगर क्षेत्र से उनका विशेष लगाव है और यहां आने पर उन्हें बड़े भाई के घर जैसा अपनापन महसूस होता है। उन्होंने विनय तिवारी एवं उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का

अनुशासन, समर्पण और समाज के प्रति सेवा भाव प्रेरणादायी है। साथ ही उन्होंने उमेश पांडेय द्वारा स्थापित आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद विधायक पप्पू पांडेय एवं विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने संयुक्त रूप से राज सिटी स्कैन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि यह सेंटर फाजिलनगर सहित आसपास के क्षेत्रों और बिहार के सीमावर्ती जिलों के मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। यहां एक ही स्थान पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। विधायक पांडेय ने बताया कि उद्घाटन के समय वे उपस्थित नहीं हो सके थे, लेकिन अब सेंटर का निरीक्षण कर उन्हें प्रसन्नता हुई है। उन्होंने सेंटर के संचालकों उमेश पांडेय एवं मोहन पांडेय को इस जनोपयोगी कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विनय तिवारी, ब्रजेश पांडेय, मनीष तिवारी, सुनीता शाही, इंद्रजीत कुशवाहा, मनोज श्रीवास्तव, विकास पांडेय, अमरनाथ पांडेय, ओमप्रकाश रौनियार, मनीष चंद्र कौशिक, चिंटू उपाध्याय, सुबोध मणि त्रिपाठी, बबलू राय, सुनील महंथ, प्रदीप राय, अमलेश तिवारी, राणा प्रताप सिंह, केदार सिंह, श्याम बिहारी पांडेय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

एक अप्रैल से धूल और मलबा फैलाने पर होगी कार्रवाई, सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबे का गलत तरीके से निपटान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक हैं। इनसे निकलने वाली धूल हवा में पीएम10 और पीएम2.5 कणों की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। खासकर सर्दियों के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। सीएक्यूएम के सदस्य-सचिव तरुण कुमार पिथोड़े के अनुसार, नए नियमों के तहत नगर निगम और विकास प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। हर 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक कचरा संग्रह केंद्र बनाना अनिवार्य किया गया है, जहां निर्माण और तोड़फोड़ से निकला मलबा जमा किया जाएगा। इसके अलावा, 200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर निर्माण या पुनर्निर्माण शुरू करने से पहले बिल्डरों को यह बताना होगा कि कितनी मात्रा में मलबा निकलेगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण शुरू करने से पहले सारा मलबा निर्धारित जगह पर जमा कर दिया गया है और उसकी रसीद प्राप्त की गई है। नए नियमों के अनुसार, बिना मलबा जमा करने की रसीद के किसी भी परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, परियोजना पूरी होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने से पहले भी संबंधित एजेंसियां इस रसीद की जांच करेंगी। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री और मलबे को ढककर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए। तरुण कुमार पिथोड़े के अनुसार, निगरानी को मजबूत बनाने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल पर कचरा संग्रह केंद्रों की जानकारी, उनकी लोकेशन (जियो-टैगिंग) और मलबा ढोने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत जुर्माना और अन्य दंड भी लगाए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने और निर्माण मलबे के बेहतर प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों के बावजूद एनसीआर के कई राज्यों में वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स (डब्ल्यूसीपी) की कमी बनी हुई है। आंकड़ों से पता चला है कि कई क्षेत्रों में तय मानकों के अनुसार कचरा संग्रह केंद्र अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। निर्देशों के अनुसार, हर 5म5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वेस्ट कलेक्शन पॉइंट होना जरूरी है, ताकि निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को सही तरीके से इकट्ठा और निपटाया जा सके।

केरल स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों में फंसा- मोदी

एलडीएफ-यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी, इन्हें भाजपा से डर; सत्ता में आते ही काले कारनामे खुल जाएंगे

तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पलक्कड़ पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री पारंपरिक केरल मुंडु (धोती) पहने हुए नजर आए। जनसभा में पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने केरल के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र चेंडा (ड्रम) पर अपना हाथ आजमाया। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ चेंडा बजाया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार उन्हें केरल में एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि केरल इस बार बदलाव का संदेश भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा पर लोगों का भरोसा अब साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद भीड़ के उत्साह को देखकर कहा कि पलक्कड़ का यह मिजाज अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल के युवा, महिलाएं और किसान अब भाजपा और एनडीए पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय केरल की जनता के आशीर्वाद और भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने केरल में राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री ने केरल की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा कि इसे सुंदरतम क्यों कहा जाता है, इसका एहसास पलक्कड़ आते ही हो जाता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल दशकों से स्वार्थी

राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ को भ्रष्ट और महाभ्रष्ट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों गठबंधनों की नीतियां केवल वोटबैंक के लिए होती हैं और इन्हें विकास की कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों ने दशकों तक केरल को लूटा और आपस में लाभ बांटा है। इनके बीच समझौता था कि कुछ साल एक सरकार चलाएगी और फिर दूसरी।प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया कि ये दोनों पार्टियां भाजपा से डरती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा सत्ता में आई तो उनके काले कामों का पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये दल देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में एक साथ गठबंधन में हैं, लेकिन केरल में एक-दूसरे को बुरा-भला कहकर जनता को धोखा दे रहे हैं।

जनता को दी मोदी की गारंटी

केरल में भाजपा और एनडीए की टीमें सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। केरल की जनता के आशीर्वाद से हम यहां सरकार बनाएंगे। एनडीए का लक्ष्य लोगों के सपनों को साकार करना है। हमने केंद्र में रहते हुए भी केरल के विकास का पूरा प्रयास किया है। अगर राज्य में भाजपा सरकार आई तो इनके सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और केरल की जनता को न्याय दिलाएगी। पीएम ने कहा, केरल में बनने वाली एनडीए सरकार राज्य का तेज विकास करेगी और यह मोदी की गारंटी है।

पश्चिम एशिया पर कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस समय पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क में हूं। सारे देश युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस संवेदनशील मामले में कांग्रेस किस तरह राजनीति कर रही है वह भी आपको याद रखना है, कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वह खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके।

गुजरात में दलित-आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप, राहुल गांधी ने उठाया ऊना कांड का मुद्दा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नफरत, भेदभाव और हिंसा का माहौल लगातार फैलता जा रहा है। राहुल गांधी ने 2016 के ऊना कोड़े मारने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। उस समय चार दलित युवकों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया था। उन्होंने कहा कि करीब एक दशक बीत जाने के बावजूद पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है, जो अपने आप में एक बड़ी विफलता है। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात से आए दलित और आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई पीड़ितों की आपबीती सुनी। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में लोगों को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनके शरीर में कई फ्रैक्चर हो गए, वहीं एक अन्य मामले में व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ अलग-अलग अपराध नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे माहौल की तस्वीर पेश करती हैं जहां डर और अन्याय हावी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें धमकियों, हिंसा और यहां तक कि हत्या के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा शासित गुजरात में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा मैं पहले भी इन परिवारों के साथ खड़ा था, आज भी हूं और तब तक उनकी आवाज उठाता रहूंगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कहा कि ऊना के पीड़ित पिछले 10 वर्षों से न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च : 3,300 जगह प्रदर्शन

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ हुए 'नो किंग्स रैली' में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रम्प सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की।

असम चुनाव : खरगे ने कांग्रेस की पांच गारंटियों का किया एलान, महिलाओं को मासिक मदद और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा

नई दिल्ली। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को राज्य के लखीमपुर जिले के नाओबोइचा में आयोजित रैली में कांग्रेस की ओर से 'पांच गारंटी' का एलान किया। इन गारंटियों में महिलाओं, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार और जस्टिस जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है।

महिलाओं के लिए मासिक सहायता का वादा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने नकद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें 50,000 रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसफर बिना किसी शर्त के होगा।

सभी परिवारों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा

खरगे ने घोषणा की कि कांग्रेस

सरकार बनने पर राज्य के सभी परिवारों को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,250 रुपये देने का भी वादा किया गया।

भूमि अधिकार और अन्य वादे

कांग्रेस ने 10 लाख स्वदेशी लोगों को स्थायी भूमि पट्टा देने का वादा किया है। इसके अलावा जुबीन गर्ग मौत मामले में 100 दिनों के भीतर न्याय सुनिश्चित करने की भी बात कही गई।

भाजपा सरकार पर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। खरगे ने कहा कि भाजपा असम में अपनी डबल इंजन सरकार का उपयोग दिल्ली में अपने नेताओं की तिजोरी लूटने और भरने के लिए कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत

महिलाओं के खाते में पैसे, 25 लाख का कैशलेस इलाज... असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 गारंटी का किया ऐलान हिमंता असम के लोगों को डराता-धमकाता है: खरगे

बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा। खरगे ने सरमा को नकली मुख्यमंत्री बताया। खरगे ने कहा कि भाजपा ने दो हजार इक्कीस का चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा था। लेकिन चुनाव के बाद, सरमा ने आदिवासी नेता सोनोवाल को असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए हटा दिया। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरमा की सरकार लोगों को डरा रही है। वह भय का माहौल बना रही है और राज्य के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है।

असम में गरजे अमित शाह, बोले- बीजेपी सरकार बनी तो 5 साल में हर घुसपैठिया होगा बाहर

असम। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सोनितपुर जिले की ढेकियाजुली विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने असम की सुरक्षा, रोजगार और विकास को मुख्य मुद्दा बनाया। शाह ने जनता से अपील की कि वे केवल मुख्यमंत्री या मंत्री चुनने के लिए नहीं, बल्कि असम को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए वोट दें। अमित शाह ने स्वीकार किया कि हालांकि पिछले दस वर्षों में नई घुसपैठ को रोकने में सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कई अवैध लोग राज्य में मौजूद हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है, तो अगले पांच वर्षों में हर घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। शाह ने कहा कि ये घुसपैठिए असम के युवाओं के रोजगार और संसाधनों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में असम ने केवल बम धमाके और हिंसा देखी थी। इसके विपरीत, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने असम को आतंकवाद से मुक्त किया है और लगभग 10,000 युवाओं को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आज का असम शांति और बड़ी इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ रहा है। शाह ने देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय पाकिस्तान से आतंकी आकर धमाके करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार है। उन्होंने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और

पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे आतंकियों का सफाया किया गया। उन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से सवाल किया कि क्या वे घुसपैठियों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ। अमित शाह ने गोपीनाथ बोरदोलोई और भूपेन हजारिका जैसे असम के दिग्गजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बोरदोलोई जी ने असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलने से बचाया था, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। यह सम्मान उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिला। इसी तरह भूपेन दा को भी मोदी सरकार ने ही भारत रत्न से सम्मानित किया।

बंगाल में भाजपा आई तो मछली-मीट खाना हो जाएगा बंद - सीएम ममता ने साधा निशाना, लगाए कई गंभीर आरोप

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में सियासी पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जनता की थाली और उनकी संस्कृति को ढाल बनाकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो यहां के लोगों का खान-पान पूरी तरह बदल दिया जाएगा।

ये लोग अपनी मर्जी का खाना थोपते हैं- सीएम ममता

एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दीदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती है।

वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। मैं आप सबको सावधान कर रही हूं कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आ गई, तो आप लोग यहां चैन से मछली, मांस या अंडा भी नहीं खा पाएंगे। ये लोग अपनी मर्जी का खाना दूसरों पर

थोपते हैं। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा एकतरफा सोच रखने वाली पार्टी है, जो असल में किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करती। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने और दंगे भड़काने का काम करते हैं। ये लोग दंगे करवाकर ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं। मासूम और बेगुनाह लोगों की जान लेकर ये लोग सत्ता का सुख भोगते हैं।

भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों पर हो रहे हमले- सीएम ममता

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं। वहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। बंगाल की अस्मिता और बंगाली प्रवासियों का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी ने एक अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में हमारे बंगाली बोलने वाले भाई-बहनों को निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ है। हम बंगाल में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते और न ही किसी पर किसी तरह का कोई अत्याचार करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि माताओं-बहनों को लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है। टीएमसी रहेगी तभी आपको यह मिलेगा। भाजपा आएगी तो चुनाव से पहले आपको कुछ पैसे देगी लेकिन चुनाव के बाद बंद कर देगी। आपको यह 1 दिन चाहिए या आजीवन चाहिए? हमने इसे आजीवन कर दिया है, जिससे माताओं-बहनों को आजीवन लक्ष्मी भंडार का पैसा मिले।

ईरान जंग पर पाकिस्तान की 3 देशों के साथ मीटिंग: सऊदी-तुर्किये और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे, अमेरिका ने 3500 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे

तेल अवीव।

ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस बैठक को होस्ट कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है। इसके साथ ही इशाक डार तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगे। यहां वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी पेशकश भी कर चुका है। उसने ईरान को 15 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव भी सौंपा है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना, मिसाइल कार्यक्रम घटाना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स से

समर्थन रोकना और सैंक्शन्स में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली करीब 3,500 सैनिकों (मरीन और नेवी) के साथ इस इलाके में पहुंच गया है।

पाकिस्तान में क्यों हो रही मीटिंग

पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसलिए पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बेहतर जगह माना जा रहा है। यह मीटिंग पहले तुर्किये में होनी थी, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान इस समय किसी एक पक्ष में सीधे शामिल नहीं है, इसलिए उसे न्यूट्रल जगह माना जा रहा है। उसके ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए बातचीत आसान है। तुर्किये और मिस्र जैसे देशों के साथ भी पाकिस्तान के संबंध ठीक हैं।

ईरान बोला- अमेरिकी सैनिक आए तो जला देंगे

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो उन्हें जला दिया जाएगा।

संसद स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि उनकी सेना अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर आने का इंतजार कर रही है और उन्हें कड़ा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में 2500 अमेरिकी मरीन की तैनाती से तनाव बढ़ा है। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है।

दादरी में अखिलेश यादव का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार आई तो 40 हजार रुपये की सम्मान राशि देंगे

दादरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार (29 मार्च) को गौतमबुद्धनगर के दादरी में रैली में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. महिलाओं के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं को स्त्री समृद्ध सम्मान योजना चलाकर 40000 सम्मान राशि देंगे.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले ये बेईमानी से चुनाव और उपचुनाव जीतते थे. अब इनकी 420 थी. इन्होंने फेक एनकाउंटर कराए, आज वो अधिकारी भी दुखी है. क्योंकि उनको पता है कि जब अदालत सजा देती है तो अकेले सजा भुगतनी पड़ती है. सपा चीफ ने कहा कि हाल ही में जो एसआईआर हुआ वो एनआरसी था. उन्होंने आगे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है. ये एक ड्राइक्लीन की दुकान है. जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर इकट्ठा हो रहे हैं. लूट भ्रष्टाचार करके भाजपा उनको शामिल करने जा रही है. यह सभी झूठ बोलते हैं.

15 लाख के वादे पर बीजेपी को घेरा

सपा चीफ ने कहा कि जब ये कहते हैं कि 15 लाख रुपए, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे,

छुट्टा पशुओं से छुटकारा देंगे तो समझ लेना झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए और पाला बदल लें. हम पाला बदलने वालों पर भी नजर रख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि नौकरी देना

इनके एजेंडे में कभी नहीं था. इसलिए ये पेपर लीक करते हैं. हम सरकार में आने पर पूरी तरह फेल खोलेंगे.

अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहा?

अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हम अग्निवीर को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. टैक्नोलॉजी से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन लड़ाई वहीं जीती जाती जहां सैनिक आगे बढ़ते हैं. जब हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर देंगे.

बीजेपी पर लगाया आरोप

बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम नोएडा से आगरा तक साइकिल यात्रा लेकर के गए थे तो इन्होंने हमें सड़क पर चढ़ने भी नहीं दिया. तभी हमने तय किया था कि हम इसका उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन भी किया और आगरा से लखनऊ और गाजीपुर तक लेकर गए. उन्होंने आगे कहा कि इनका.गुरुवाला एक्सप्रेस बन रहा है जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. हमने सड़कें दीं. सबसे बेहतर पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम दिया. बच्चों को भोजन दिया, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया और अब स्कूल भी बंद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो 1090 से बेहतर स्कीम लाएंगे.

पीएम मोदी के हमले पर किया पलटवार

पीएम मोदी द्वारा किए गए हमले पर बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास नोएडा में ही किया. उस वक्त कोई अंधविश्वास नहीं था. इस बार उम्मीद से ज्यादा एसपी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है. नोएडा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं. लोगों की पुकार है कि बीजेपी सरकार से हट जाए. उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जिन लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं. वो सब वापस लिए जाएंगे. भाजपा वाले डायलॉग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया नहीं है तो वो कहते हैं कि एक तो माफिया है. सरकार बनने के बाद खुद के और अपनों के केस वापस लिए, इसलिए 9 साल का हिसाब नहीं है. इसी वजह से आधे अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए. उन्होंने आगे बताया कि एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम हमने किया. अभी तो एक ही फेज बना है. आगे भी बनेंगे. हमारी सरकार बनेगी तो कोई भेदभाव नहीं होगा. बाजार पर 64 फीसदी का मुआवजा और 4फीसदी प्लॉट देंगे.